with the implementation of that part of the report by the State Governments? What will the Government of India do to co-ordinate it?

Shri Karmarkar: As I said, there are certain aspects of the report which concern our work, as for instance, the contributory health service scheme. The State Governments have nothing to do with that. There are certain aspects like medical relief in the States with which we have nothing to do. Therefore, we have divided the report into two portions. We are sending that part of the report which relates to the State Governments—action to be taken by them—to the State Governments. We are taking speedy action to consider or implement that part of the report which concerns us.

उत्तर प्रदेश में दूर-संचार व्यवस्था का पुनर्गठन

*१०२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न-संख्या ६७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिमण्डल के डाक-तार विभाग में दूर-संचार व्यवस्था को पुनर्गठित करने तथा अतिरिक्त मण्डल व उप-मण्डल बनाने की दिशा में इस बीच और कौन से कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : तीन और इंजीनियरी मण्डलों और दो और उप मण्डलों की मंजूरी दे दी गई है । वे इस प्रकार हैं :—

इंजीनियरी मण्डल	उप मण्डल
इलाहाबाद फोन	लखनऊ पश्चिम तार
मेरठ फोन	मेरठ टेलीफोन
बरेली तार	—

लखनऊ-कानपुर दूर-संचार क्षेत्र का पुनर्गठन करने का भी विचार है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या सारे मंडल या सरकिल के बारे में कोई चित्र तैयार किया गया है कि कितनी आवश्यकता है, और क्यों नहीं एक ही बार में इसका पुनर्गठन कर लिया जाता और बार बार निर्णय क्यों लिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : जैसे जैसे अनुभव होता है उसी के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं । एक बार में सब का निर्णय लेना मेरे ख्याल में सम्भव भी नहीं है, और न यह व्यवहारिक या मितव्ययी होगा ।

SHORT NOTICE QUESTIONS

गेहूं के मूल्य निश्चित सीमा से न गिरने देना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के मूल्य निश्चित सीमा से न गिरने देने (प्राइस सपोर्ट) के लिये बनाई गयी योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ख) गेहूं के मूल्य न गिरने देने (प्राइस सपोर्ट) से जो धन प्राप्त होगा, वह का तकार तक किस प्रकार पहुंचेगा; और

(ग) यह योजना कब से लागू की जायेगी?

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): (a) In pursuance of their policy to assure a reasonable price to the cultivator for his produce, Government of India have fixed a minimum support price of Rs. 13 per maund for fair average quality of common varieties of white wheat for the 1961-62 wheat crop. Government are making necessary arrangements in consultation with the State Governments to undertake purchase operations in case the prices of wheat tend to fall below the minimum price.

(b) The minimum price for wheat has been fixed to assure the cultivator of a reasonable return for his produce, in order that he may have the necessary incentive to make the requisite investment in agriculture

and put in larger effort to produce more.

(c) The scheme would be applicable to the 1961-62 wheat crop which is about to be harvested.

श्री खुशवक्त राय: मैं जानना चाहता हूं कि गल्ले की खरीद कब से शुरू की जाएगी, जब दाम देहात में गिरने लगेंगे तब से या जब दाम शहरों में गिरने लगेंगे तब से?

श्री स० का० पाटिल: खरीदने का तो विचार नहीं है। जब प्राइस १३ रुपए से नीचे गिर जाएगी तभी गवर्नमेंट खरीदने के लिए आएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार पहले से खरीदने लगे।

श्री खुशवक्त राय: मैं यही जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट परचेज करेगी तो वह कहां करेगी, देहात के बाजारों में या शहर के बाजारों में?

श्री स० का० पाटिल: वह तो स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके निश्चय करना होगा।

Shri Tyagi: Have the Government made sure that Rs. 13 per maund is a rate which is not uneconomic to the farmer, for, as far as I know, this is no where as far as the expenditure ratio is concerned?

Shri S. K. Patil It is called and rightly so the minimum price support. It does not mean that Government do not expect the farmer to get a little more than that. But there are instances where, when the new crops come in, the prices go down in the villages and the farmer does not know whether he is likely to get a better price. Therefore, he has got to be supported. So, a beginnig has been made by giving him an irreducible minimum. That does not mean that the price cannot be a little more than that.

Shri Kasliwal: The Minister said that for the moment, he has given price support to wheat. May I know whether Government are considering any price support to any other agricultural commodity whose price may tend to fall?

Shri S. K. Patil: The very fact that we have begun with wheat shows that the Government is prepared to do it not only for any other particular crop, but the whole range of agricultural production.

Shri Shivananjappa: What are the new formulae evolved to pay extra price over and above the statutory price?

Shri S. K. Patil: The question is about wheat.

श्री ब्रजराज सिंह: जिन आधारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है कि १३ रुपए मन से कम पर गेहूं नहीं बेचा जाएगा, क्या उन आधारों को निश्चित करते वक्त यह भी ख्याल किया गया था कि एक मन गेहूं पैदा करने में किसान को कितना खर्चा करना पड़ता है और उसकी जिन्दगी के गुजारे के लिए उसको कम से कम कितनी कीमत की जरूरत है?

श्री स० का० पाटिल: वह तो यह नहीं है। उसके लिए तो मैं ने दो चार बार हाउस में कहा है कि उसके लिए तो एक कमेटी नियुक्त करनी होगी क्योंकि वह कोई सीधा सादा सवाल नहीं है। और फिर गेहूं ही तो एक चीज नहीं है, इतनी सारी एग्रीकल्चुरल कमेडिटीज हैं, उन सब का क्लेम ध्यान में रखना होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं इस वक्त नहीं दे सकता क्योंकि कोई साइंटिफिक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। लेकिन १३ रुपया जो रखा गया है उसका अर्थ यह नहीं है कि यह इकानमिक प्राइस है। यह तो मिनिमम प्राइस रखी है कि इससे नीचे गेहूं की कीमत नहीं जाएगी। जब वक्त आएगा तो इस चीज की पूरी जांच की जाएगी। और उस वक्त यह कीमत बढ़ भी सकती है।

श्री ब्रजराज सिंह: जिस कमेटी का जिक्र खाद्य मंत्री महोदय ने किया उसके बारे में वह

पिछले चार पांच साल से कहते आ रहे हैं। किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए कमेटी नियुक्त करने में सरकार कितनी देरी और लगाएगी। कितने समय में सरकार इस कमेटी को बनाने का विचार करती है?

श्री स० का० पाटिल : यह जो १३ रुपए मन है यह तो मिनीमम प्राइस सपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट की स्कीम को मंजूर करती है। शायद १३ रुपये का फिगर बदल जाये और इस से ज्यादा हो जाये। लेकिन इस के लिये जो कमेटी मुकर्रर की जायेगी उस में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वह एक बड़ी चीज है और उस को सारी एग्रीकल्चरल कमेटीज पर विचार करना होगा।

श्री सिंहासन सिंह : गवर्नमेंट दो बरस से यह कहती आ रही है कि वह प्राइस सपोर्ट की पालिसी के बारे में एक कमेटी बनायेगी। अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि अभी उस में कुछ समय लगेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रोअर्स के हितों के बारे में और उन की उपज के बारे में गवर्नमेंट कब तक निश्चय कर सकेगी और कब तक उन की उपज की उचित कीमत निश्चित की जायेगी ताकि वे समुचित तौर से अपनी खेती कर सकें। इस में कितना समय और लगेगा?

श्री स० का० पाटिल : प्राइस सपोर्ट तो अभी शुरू हो गया लेकिन उस पर डिटेल में अभी विचार करना है। अभी उस के लिये कमेटी बनाने में कुछ समय लगेगा। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि वह इकानामिक प्राइस है या नहीं और कितनी इकानामिक प्राइस हो सकती है। यह पेचीदा सवाल है और इस लिये इस का यकायक जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिये मैं ने कहा कि इस के लिये एक सांइटिफिक कमेटी बनायी जायेगी जो सब चीजों की जांच करेगी और निश्चित करेगी कि हर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिये क्या इकानामिक प्राइस हो सकती ह।

श्री सिंहासन सिंह : मेहता कमेटी के बाद से प्राइस सपोर्ट की बात चल रही है और गवर्नमेंट हमेशा यह उत्तर देती है कि इस के लिये कमेटी बनायी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कब तक बन जायेगी।

श्री स० का० पाटिल : एग्रीकल्चर तो हिन्दुस्तान में सौ बरस से चल रहा है। अभी यह बात दो बरस से चल रही है। इस पर विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह इतनी सीधी बात नहीं है कि इस पर दो मिनट या दो महीने में निर्णय लिया जा सके। इस में थोड़ा समय लगेगा।

श्री वाजपेयी : सस्ते अनाज की जो सरकारी दुकानें हैं उन पर गेहूं १४ रु० मन के हिसाब से बेचा जा रहा है, और सरकार १३ रुपये मन के भाव से न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रही है। क्या यह मूल्य निर्धारित करते समय जिस भाव पर हम को विदेशों से गेहूं मिल रहा है उस पर भी विचार किया गया है?

श्री स० का० पाटिल : उस पर विचार किया गया है और मैं ने कहा कि यह इकानामिक प्राइस नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि किसान को इस से ज्यादा मिल लेकिन अगर किसी मंडी में गेहूं ज्यादा आ जाने से प्राइस गिरने लगती है तो गवर्नमेंट यह गारन्टी देती है कि वह १३ रुपये से ज्यादा उसे नहीं गिरने देगी और खुद खरीदना शुरू कर देगी।

Shri Tyagi: Is there any secret plan in the sleeves of the hon. Minister to get wheat very cheap in the market very soon? Are they going to have very cheap wheat in the market and that is why they are taking these precautions? Is there any such thing in the offing?

Shri S. K. Patil: There is no secret plan that the Minister cannot disclose

to the House. After all, the sanction of this House is necessary for anything that is being done. So far there is no secret plan. This is merely being done because there is a persistent demand from the farmer that he must be protected in the event of production being more and when the surplus agricultural economy is likely to come. Such guarantees are given by every Government in the world and I think it is a welcome sign that the Government of India have done it.

Supply of Rice in Kerala

S.N.Q. 2. + **Shri A. K. Gopalan:** / **Shri Kunhan:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the quantity of rice supplied through fair price shops in Kerala has been reduced from 2½ measures to 1½ measures recently;

(b) if so, the reasons for the reduction;

(c) what is the quantity of rice supplied to Kerala from Centre during each of the last 12 months; and

(d) whether there has been any reduction in the quantity recently?

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): (a) and (b). The quantities of rice supplied through fair price shops and supplied to Kerala depend on the availability of rice in the local market. Generally, the quantum of ration is reduced during the post-harvest period and enhanced during the lean season. Following this practice, the quantity of rice issued through fair price shops in Kerala has been reduced from 2 measures to 1 measure per family per week with effect from the 4th March, 1962.

(c) A statement showing the supplies of rice made to Kerala from Central stocks during each of the months from March 1961 to February 1962 is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Month	('000 M. Tonnes)
March, 1961 ..	8.4
April, 1961 ..	5.7
May, 1961 ..	12.5
June, 1961 ..	22.2
July, 1961 ..	31.6
August, 1961 ..	30.9
September, 1961 ..	14.2
October, 1961 ..	24.6
November, 1961 ..	23.8
December, 1961 ..	26.6
January, 1962 ..	26.3
February, 1962 ..	23.8
Total	250.6

(d) The monthly supplies to Kerala from Madras onwards would be reduced on account of the reduction in the quantum of ration referred to above.

12.10 hrs.

Shri A. K. Gopalan: According to the statement the quantity was reduced in February, whereas in January, December, November, June and July the quantity was more. May I know whether this reduction was due to the availability of rice from the crop?

Shri S. K. Patil: As far as my information goes, during the harvest months the quantity is reduced every year. This is not a new phenomenon. In the lean period it is increased. The figures also show a corresponding increase in production. If there is any difficulty or hardship on that account, surely I am prepared to examine it. As I said, it is a normal feature.

Shri A. K. Gopalan: May I know whether the State Government has requested the Centre for supply of rice; if so, for how much?

Shri S. K. Patil: I do not think so, because this correspondence goes on month after month. So far as the rice situation is concerned we are in a happy position and the State is not in any difficulty at all. So far as the availability of rice is concerned, I